भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 262

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति

***262. श्री मनीश तिवारीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के मुख्य उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं;

(ख) पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए इस नीति के तहत आरंभ की गई विशिष्ट पहल और कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) ऐसे पड़ोसी देशों का ब्यौरा क्या है जिनकी स्पष्ट "इंडिया फर्स्ट" नीति है;

(घ) क्या बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में शासन परिवर्तन से उन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर, विशेषतः चल रही परियोजनाओं और रणनीतिक साझेदारी पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, विशेषतः भारत के निकटतम पड़ोसी देश चीन से भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न चुनौतियों से कैसे निपटने की योजना है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

‘भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति' के संबंध में दिनांक 13.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *262 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

(क) से (च): ‘पड़ोस प्रथम’ नीति, जो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंधों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है, में वास्तविक, डिजिटल और लोगों के बीच पारस्परिक कनेक्टिविटी के निर्माण द्वारा, स्थिरता एवं समृद्धि हेतु पारस्परिक रूप से लाभकारी, जनोन्मुख, क्षेत्रीय संरचनाएं तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत इन देशों के साथ परामर्शात्मक, गैर-पारस्परिक और परिणामोन्मुख आधार पर कार्य करता है, जो सम्मान, संवाद, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों से प्रेरित है।

भारत की ‘पड़ोस प्रथम’ नीति के तहत, सरकार पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार आवश्यक विकास सहायता प्रदान कर रही है और क्षमता निर्माण संबंधी पहलें कर रही है, जिससे इन देशों के समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिल रही है। इस दृष्टिकोण के तहत, भारत पड़ोसी देशों को अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के विकास में सहायता कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अवसंरचना से लेकर समुदाय संबंधी परिसंपत्तियां और मंच उपलब्ध करना, क्षमताओं का संवर्धन करना तथा वित्तीय, बजटीय और मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

इस नीति के तहत भारत द्वारा बहुत बड़ी संख्या में पहलें और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) अफगानिस्तान को खाद्य और चिकित्सा सहायता के रूप में मानवीय सहायता, तथा अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं;

(ii) बांग्लादेश में सीमा पार बिजली, ऊर्जा और परिवहन संपर्क के क्षेत्रों में अनेक विकास सहयोग परियोजनाएं;

(iii) भूटान को क्षमता निर्माण और उसके जलविद्युत संसाधनों के विकास तथा ऊर्जा, रेल संपर्क, सड़क, व्यापार अवसंरचना और डिजिटल संपर्क सहित सीमा पार कनेक्टिविटी संपर्क हेतु सहायता;

(iv) मालदीव के साथ सहयोग वित्तीय अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायता के अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, लोगों के बीच आदान-प्रदान और सामुदायिक निर्माण संबंधी अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन पर केंद्रित रहा है;

(v) म्यांमार को मानवीय राहत और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में सहायता के अतिरिक्त अनेक कनेक्टिविटी अवसंरचना विकास परियोजनाओं और क्षमता निर्माण हेतु सहायता;

(vi) नेपाल के साथ विकास सहयोग का एक अति व्यापक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, तथा आर्थिक, ऊर्जा, डिजिटल और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है, जिसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता, जल निकासी, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल विद्युत, तटबंध और नदी प्रशिक्षण कार्यों के निर्माण में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) का कार्यान्वयन शामिल है ताकि स्थानीय स्तर पर जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

(vii) श्रीलंका के साथ सहयोग, जिसमें कनेक्टिविटी, कृषि, बिजली, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और आर्थिक संबंध तथा एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम शामिल है।

भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत इसकी सहायता को हमारे पड़ोसी देशों के लोकमत से जुड़े विभिन्न वर्गों द्वारा मूल्यवान माना जाता है, जिससे इन देशों के प्रशासन में होने वाले परिवर्तन के बावजूद इन सहायता कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए एक स्थायी आधार सुनिश्चित होता है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापक और दीर्घकालिक संबंध भी अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा ये संबंध अन्य देशों के साथ इन देशों के संबंधों से निरपेक्ष हैं। सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की सुदृढ़ और स्थायी प्रकृति के बारे में आश्वस्त है और पारस्परिक लाभ हेतु द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

*****